INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Corporate Identity Number : L74899DL1984PLC019218
Regd Office : MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002
Phones: 41519433, 41520070 Fax : 41503479
Website :www.indialease.com E-mail : info @indialease.com

No. BSE/2020-2021/016

August 14, 2020

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Company Code: 500202

Re: Copy of press release of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

Dear Sir,

In continuation to our letter dated August 13, 2020 regarding submission of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020. The said results were being published and the copy of the same is enclosed for your kind perusal.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For India Lease Development Limited

Rohit Madan
Manager, Company Secretary & CFO

Encl: As above

कैदी ने 52 अन्य कैदियों को अंतरिम जमानत दिलाने को किया फर्जीवाड़ा

पुलिस की जांच में खुला बड़ा राज

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अगस्त

लॉकडाउन के दौरान अंतरिम जमानत पर कैदियों को रिहा करने के अदालती फैसले को एक कैदी ने अपना कारोबार बना लिया। पुलिस के मुताबिक, उसने पहले खुद अंतरिम जमानत प्राप्त की और फिर जेल से बाहर आने से पहले ही अन्य कैदियों को जमानत दिलाने के नाम पर सौदेबाजी शुरू कर ली। इस कैदी ने कथिततौर पर उन कैदियों के घर के पते लिए और फिर उनके रिश्तेदारों को गंभीर बीमारी के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करा लिए। पुलिस जांच में अब तक ऐसे 52 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अदालत को बताया कि एक आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका के साथ लगाए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच के दौरान पूरा मामला खुला। दरअसल, इस कैदी की पत्नी के गर्भाश्य में गांठ होने की बात कहकर तत्काल ऑपरेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया था। अदालत के आदेश पर जांच अधिकारी जब इस मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच करने पहुंचा तो पता चला कि जिस अस्पताल के नाम पर यह सर्टिफिकेट जारी है। वहां सिर्फ तीन बेड थे और वहां ना तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था

थी और ना ही कोई ऑपरेशन की सुविधा। पुलिस के मुताबिक, यहां से शुरू हुई जांच से पता चला कि इसी एक डॉक्टर के नाम से दिल्ली की अलग-अलग जिला अदालतों में 52 से ज्यादा मुकदमों में कैदियों के रिश्तेदारों को गंभीर बीमारी व उनका तत्काल ऑपरेशन कराने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कैदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जिस कैदी ने धोखाधड़ी व जालसाजी का यह पूरा जाल बुना, उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। यह कैदी नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार व पॉक्सो के तहत वर्ष 2014 से तिहाड़ जेल में बंद था। हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर इस कैदी को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई थी। हालांकि, आरोपी कैदी का कहना है कि वह इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस की तरफ से अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के मुताबिक जमानत मिलने के बाद से लगातार वह कथिततौर पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर के संपर्क में था। पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोपी के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश किया। पुलिस का दावा है कि यह मुख्य आरोपी ही उन कैदियों के घर तक आरोपी डॉक्टर से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर पहुंचाता था। इस कैदी ने जेल से बाहर आने से पहले ही इन कैदियों से जमानत दिलाने के नाम पर सौदेबाजी कर ली थी। उनके घर के पते भी ले लिए थे। पुलिस का कहना है कि जांच में वह साक्ष्य जुटा लिए गए हैं जिनमें पता चलता है कि वह खुद कैदियों के घर यह फर्जी सर्टिफिकेट देने जाता था। दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत को यह भी जानकारी भी दी गई कि शुरू में इस मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब इस मामले में आपराधिक साजिश की अतिरिक्त धारा भी जोड़ दी गई है। अगर आपराधिक साजिश का आरोप साबित होता है तो आरोपियों को अधिकतम उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने आरोपी डॉक्टर के गैरकानूनी आचरण के मद्देनजर उसकी प्रैक्टिस पर 29 नवंबर 2020 तक रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके इसी डॉक्टर के नाम से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिल्ली की अलग-अलग जिला अदालतों में अंतरिम जमानत का आधार बनाते हुए लगाए गए हैं।

आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने पर 'आप' के पूर्व विधायक जरनैल सिंह सस्पेंड

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अगस्त

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने पूर्व विधायक जरनैल सिंह को हिंदू देवी-देवताओं पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, जरनैल सिंह ने दावा किया है कि वह पोस्ट गलती से उनके छोटे बेटे द्वारा की गई थी जो एक ऑनलाइन क्लास के दौरान उनका फोन चला रहा था।

उन्हें सस्पेंड करने का फैसला 11 अगस्त को पार्टी की पीएसी में लिया गया था। यह बात 'आप' के तिलक नगर विधायक और पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कही है। फेसबुक पोस्ट के अनुसार, राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक जरनैल सिंह को आम आदमी पार्टी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है। जरनैल सिंह (पूर्व विधायक) द्वारा 11.08.2020 को हिंदू देवी-देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 'आप' की पीएसी की बैठक में उनके सस्पेंशन का फैसला लिया गया। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि इस घृणित कार्य के लिए उन्हें क्यों पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।

यह कहते हुए कि आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तिलक नगर विधायक ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान करने वाले के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है।

सिख समुदाय भी उनके बयान से बहुत दुखी है क्योंकि किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं

के खिलाफ है।

आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और किसी भी धर्म का अपमान करने वाले लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक जरनैल सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा करती है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया जाता है। ह्व

हालांकि, राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि उनके बेटे ने गलती से ऑनलाइन क्लास के लिए फोन का उपयोग करते हुए यह पोस्ट कर दिया था।

> उन्हें सस्पेंड करने का फैसला 11 अगस्त को पार्टी की पीएसी में लिया गया था। यह बात 'आप' के तिलक नगर विधायक और पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कही है। फेसबुक पोस्ट के अनुसार, राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक जरनैल सिंह को आम आदमी पार्टी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है।

उन्होंने 12 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट में कहा था, कल मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए अपने छोटे बेटे के साथ अपना फोन दिया था, तभी उसने एक पोस्ट कॉपी-पेस्ट कर दिया। जो मैंने डिलीट कर दिया था। मैं भगवान राम, गोबिंद, केशव, सदाशिव के सभी नामों का सम्मान करता हूं और गुरु तेग बहादुर साहिब के सिद्धांतों का पालन करता हूं।

2009 में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर जूता फेंकने के बाद पूर्व विधायक जरनैल सिंह लाइमलाइट में आ गए थे। 2014 में, उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें वह भाजपा के प्रवेश वर्मा से हार गए थे।

प्रमुख सिख चेहरा जरनैल सिंह को बाद में 2015 में राजौरी गार्डन से दिल्ली विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में लांबी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 2017 में इस्तीफा दे दिया था।

मुकेश टोकस के निष्कासन की मांग

नई दिल्ली, 13 अगस्त

दिल्ली के आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के संगठन प्रभारी मुकेश टोकस को एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि यह बेहद ही शर्मनाक है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं तो दूसरी ओर उनके पार्टी के नेता ही दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के लिए आम आदमी पार्टी के नेता शरद चैहान, संदीप कुमार, प्रकाश जरवाल जैसे कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की महिला सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ अखबारों के 3-4 पन्नों के विज्ञापन, बड़े-बड़े होर्डिंग्स में ही दिखते हैं लेकिन हकीकत में नहीं और जब आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही नाम महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बदसलूकी, मारपीट जैसे मामलों में सामने आते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की फेहरिस्त लंबी है जिन्होंने यह साबित किया है कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे नेताओं को स्वयं संरक्षण देते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि कहा कि केजरीवाल सरकार महिला सुरक्षा व्यवस्था पर राजनीति तो जरूर करती लेकिन खुद इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जनता सुरक्षा के लिए चुना है न की अपराधियों को सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल को स्वयं ही गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लेना होगा। दिल्ली भाजपा यह मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से मुकेश टोकस को आम आदमी पार्टी से निष्कासित किया जाए और उसपर सख्त कार्रवाई की जाए।

किन्नरों ने महिला को घर ने बाहर निकालकर पीटा

नई दिल्ली, 13 अगस्त

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में किन्नरों के एक समूह ने कथित तौर पर हंगामा किया और एक महिला को उसके घर से बाहर खींचकर उसे बुरी तरह से पीटा, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि संपत्ति विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था जिसके कारण यह घटना हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) वेद प्रकाश सूर्या ने एएनआई को बताया कि मकान मालिक प्रवीण शर्मा ने अपने एक बुजुर्ग किरायेदार से कमरा खाली करने के लिए कहा था, लेकिन किरायेदार ने कमरा खाली करने से मना कर दिया।

चांदनी चौक में दिल्ली की सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू

महालक्ष्मी ब्यूरो/नई दिल्ली, 13 अगस्त

एशिया की सबसे बड़ी मार्केट चांदनी चौक में बनाई जा रही मल्टीलेवल पार्किंग दिल्ली की सबसे बड़ी पार्किंग होगी। पांच मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग में करीब 2400 कारों के अलावा टूरिस्ट बसों को भी खड़ा किया जा सकेगा। उत्तरी निगम इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसे फरवरी 2022 तक पूरा किया जाना है।

चांदनी चौक में यातायात की समस्या को कम करने और लोगों को पार्किंग सुविधा मुहैया कराने के मकसद से उत्तरी निगम ने चांदनी चौक गांधी मैदान की करीब साढ़े चार एकड़ जमीन पर मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने की योजना बनाई थी। इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पांच मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना का काम सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। प्रदूषण के कारण उच्चतम न्यायालय के आदेश पर निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से लगभग छह माह तक निर्माण कार्य में बाधा बनी रही।

बताया गया कि छह माह की बाधा के बाद मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो चुका है। परियोजना को पीपीपी मॉडल पर ओमेक्स को दिया गया है। यह कंपनी उत्तरी निगम को 250 करोड़ रुपये जमा करा चुकी है। उत्तरी निगम को लगभग 450 करोड़ रुपये का राजस्व चार किश्तों में जमा कराया जाना है, जिसमें से दो किश्त जमा करा दी गई हैं।

चांदनी चौक और उसके आस-पास के सराफा बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के लिए वाहनों को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती रहती है। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पांच मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग में करीब 2400 कारें और 100 टूरिस्ट बसें खड़ी हो सकेंगी। बताया गया कि चांदनी चौक की पार्किंग दिल्ली की पहली [illegible] बड़ी मल्टीलेवल पार्किंग होगी, जिसमें कारों के साथ-साथ ब[illegible] की जा सकेंगी।

जल्द डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे दिल्ली मेट्रो में सफर, स्मार्ट कार्ड से होगा जुमार्ने का भगुतान

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अगस्त

दिल्ली मेट्रो में आने वाले समय में सफर करने के लिए आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। डीएमआरसी अपने ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है। सबकुछ ठीक रहा तो अगले एक से डेढ़ वर्ष के अंदर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर मेट्रो की ओर से निविदा भी जारी कर दी गई है।

दिल्ली मेट्रो अपने पूरे फेयर कलेक्शन को मेट्रो फेज चार के तीन कॉरीडोर को ध्यान में रखक[illegible] अपग्रेड करने जा रहा है। [illegible] लेस सिस्टम के साथ [illegible]शन को बढ़ावा [illegible]कसद से डीएमआ[illegible] फैसला लिया

है। इसके तहत पूरे फेयर कलेक्शन सिस्टम को पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। टिकटिंग मशीन को भी पीओएस मशीन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जिससे स्मार्ट कार्ड को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कराने में भी आसानी होगी। दिल्ली मेट्रो ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम में मेट्रो नेटवर्क किराए को लेकर 32 जोन बनाए [illegible]ए हैं। अब मेट्रो के बढ़ते नेटवर्क [illegible]को देखते हुए इसे दोगुना यानि 64 किया जाएगा। मेट्रो फेज चार में तीन मेट्रो कॉरीडोर और उसके मेट्रो स्टेशन को ध्यान में रखकर यह बनाया गया है, जिससे किराया उसके आधार पर काटा जा सके। इसके अलावा मौजूदा सिस्टम में अभी 256 मेट्रो स्टेशन की क्षमता है। उसे बढ़ाने की भी जरूरत है। अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 512 मेट्रो स्टेशन किया जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो में जुमार्ने का भुगतान भी मेट्रो स्मार्ट कार्ड से कर पाएंगे। अभी तक स्मार्ट कार्ड में पैसा होने के बाद भी आपको कैश देकर ही जुमार्ना भरने का प्रावधान था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आप स्मार्ट कार्ड में मौजूद पैसे से जुमार्ने का भुगतान कर पाएंगे। यह जुमार्ना मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते समय लगता है। यह उस समय होता है, जब स्मार्ट कार्ड से पिछली बार आपका किराया नहीं काटा गया होता है या फिर जब टोकन कहीं का लेकर उससे लंबी यात्रा करते हैं। दिल्ली मेट्रो ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ पुराने आटोमैटिक फेयर कलेक्शन गेट को भी बदल रही है। ऐसी करीब 600 एएफसी गेट को चिन्हित किया गया है।

वर्दी का रौब दिखा लोगों को लूटने वाले दिल्ली पुलिस के 3 जवान बर्खास्त

नई दिल्ली, 13 अगस्त (ह.स.)

दिल्ली की वसंतकुंज थाना पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए 9 अगस्त को दिल्ली पुलिस में कार्यरत तीन जवानों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार जवानों में मोनू और अमित मालवीय नगर थाने में जबकि संदीप स्पेशल सेल में तैनात थे। आरोपियों की लूट व अन्य कई मामलों में संलिप्तता सामने आने के बाद आला अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली पुलिस से बर्खास्त कर दिया है। बुधवार को पुलिस मुख्यालय से जरूरी कार्रवाई कर तीनों के संबंध में उनसे जुड़े अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। ज्ञात हो कि 8 अगस्त को महिपालपुर के एक कारोबारी ने वसंतकुंज नॉर्थ थाने में अपने साथ बंधक बनाकर हुई लूट की शिकायत दी थी। पीड़ित कारोबारी नवीन सेहरावत ने बताया कि वह एक फर्म चलाते हैं और उसके निदेशक हैं। 8 अगस्त को वह अपने कर्मचारियों के साथ ऑफिस में काम में व्यस्त थे, तभी चार लोग मास्क लगाकर ऑफिस में पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्हें पिस्तौल दिखाकर पैसा और अन्य सामान लूट कर ले गए। हालांकि, इस दौरान ऑफिस के कर्मचारियों ने जय कपूर नामक एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया था। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट के सभी अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में तीनों पुलिसकर्मी संदीप कुमार, मनू कुमार और अमित कुमार शामिल थे। लूट की वारदात में तीनों का नाम सामने आने के बाद पुलिस आयुक्त ने तीनों आरोपियों को बुधवार शाम को पुलिस फोर्स से बर्खास्त कर दिया। वसंतकुंज नॉर्थ थाना पुलिस लूट की वारदात की जांच कर रही थी, तभी इस जांच के दौरान सामने आया कि तीनों पुलिस कर्मी इससे पहले भी लोगों को पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर उन्हें डराते थे और उसके बार-बार जबरन पैसा व अन्य सामान लूट लेते थे। आरोपियों ने कई कारोबारियों से पुलिस छापेमारी का डर दिखाकर जबरन वसूली की थी।

ILD इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड

CIN : L74899DL1984PLC019218 GSTIN : 07AAACI0149R1ZB
पंजीकृत कार्यालय : एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-110002 फोन : 41519433, 41520070 फैक्स : 41503479
वेबसाइट : www.indialease.com, ईमेल : info@indialease.com

30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिये स्वतंत्र इंड एएस अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिया गया निष्कर्ष (₹ लाखों में ईपीएस छोड़ कर)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त			समाप्त वर्ष
		30.06.2020 (अनअंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	30.06.2019 (अनअंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)
1	संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	16.43	15.14	21.83	749.62
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और / या असाधारण आइटम से पूर्व)	1.51	(10.76)	4.25	130.54
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्)	1.51	(10.76)	4.25	130.54
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि कर के पश्चात्	1.51	(10.76)	4.25	130.54
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद)	1.87	(136.75)	4.29	4.67
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02
7.	रिजर्व (पुर्न मूल्यांकित रिजर्व को छोड़कर) गत वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए गए अनुसार	-	-	-	(542.49)
8.	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 10/-रु)				
	(क) बेसिक	0.01	(0.07)	0.03	0.89
	(ख) डायल्यूटिड	0.01	(0.07)	0.03	0.89

टिप्पणी : सेबी (सूचीबद्ध एवं अन्य उद्घोषणा अनिवार्याताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज पर लगाए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत फोरमेट का एक निष्कर्ष ऊपर दिया गया है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा फोरमेट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www. bseindia.com** तथा कपनीं की वेबसाइट **www.indialease.com** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड
राजीव गुप्ता
अध्य[illegible]
DIN : 00[illegible]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2020

MGF दि मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

CIN : L74899DL1930PLC000208
रजि. आ. : एमजीएफ हाऊस, 4/17बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
ईमेल आईडी : mgfltd@hotmail.com
वेबसाइट::http://www.mgfltd.com फोन: 23272216-18, 23278001-02

30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्वतंत्र एवं संगठित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम का ब्यौरा (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्वतंत्र			संगठित		
		समाप्त तिमाही		वर्ष समाप्त	समाप्त तिमाही		वर्ष समाप्त
		30.06.2020 (अनअंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	30.06.2020 (अनअंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	30.03.2020 (अंकेक्षित)
1	संचालनों से कुल आय	22.91	350.73	996.18	22.91	350.73	996.18
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और / या असाधारण आइटम से पूर्व)	(173.62)	(289.93)	(541.34)	(173.62)	(135.35)	(386.76)
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व (एक्सेप्शनल और / या असाधारण आइटम के पश्चात्)	(173.62)	(289.93)	(541.34)	(173.62)	(135.35)	(386.76)
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर के पश्चात् (एक्सेप्शनल और / या असाधारण आइटम के पश्चात्)	(173.62)	(293.36)	(544.77)	(173.15)	(142.15)	(349.26)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद)	(170.84)	(282.90)	(534.51)	(170.26)	(131.73)	(378.46)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36
7.	सुरक्षित (पुनर्मूल्यांक आरक्षितों के अतिरिक्त) जैसा कि पूर्व वर्ष की अंकेक्षित लेखा में प्रदर्शित है।	-	-	3,568.33	-	-	3,424.49
8.	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 10/-रु) (निरंतर और बंद किए गए कार्यों के लिए)						
	(क) बेसिक (रु. में)	(0.45)	(0.76)	(1.41)	(0.45)	(0.37)	(0.90)
	(ख) डायल्यूटिड (रु. में)	(0.45)	(0.76)	(1.41)	(0.45)	(0.37)	(0.90)

नोट: 1) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं अन्य उद्घोषणा अनिवार्याताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज पर लगाए गए 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत फोरमेट का एक निष्कर्ष ऊपर दिया गया है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा फोरमेट एवं विवरण नोट्स स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.nseindia.com, www. bseindia.com** और कपनीं की वेबसाइट **www.mgfltd.com** पर उपलब्ध है।

2) उपरोक्त वित्तीय परिणाम (स्वतंत्र एवं संगठित) गुरुवार, 13 अगस्त 2020 को सम्पन्न बैठक में ऑडिट कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं, तत्पश्चात् निदेशक मंडल की गुरुवार,13 अगस्त 2020 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृत किये गये।

3) यह कथन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंडस्ट्रीज एएस), कंपनी अधिनियम (2013) और अन्य मान्यता प्राप्त लेखा प्रथाओं और नीतियों के लागू होने के हद तक के अनुसार तैयार किया गया है।

4) एक सहयोगी कंपनी, जयभारत क्रेडिट लिमिटेड के मामले में, अब एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 20 दिसंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पंजीकरण रद्द किया जाना है।

5) कंपनी ने इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य रु. 5 प्रति शेयर है, जैसा कि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पोस्टल बैलेट से 30 मार्च 2020 को, रिकार्ड तिथि 22 जून 2020 अनुमोदित हुआ। प्रति वर्ष आय के अनुसार इंडस्ट्रीज -33 के अनुसार, ऊपर दिए गए सभी वर्षों / अवधि के लिए प्रति शेयर गणना इक्विटी शेयरों की नई संख्या पर आधारित है।

6) पूर्व वर्ष/ अवधि के आंकड़े आवश्यकतानुसार जहां-तहां रिग्रुप्ड/रिअरेंज कर दिये गये हैं।

कृते द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता/-
(राजीव गुप्ता)
चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी
DIN : 00022964

स्थान : [illegible]ल्ली
[illegible] अगस्त 2020

'We fear for our lives': Residents, workers in complex complain of apathy, neglect

MM BUREAU

New Delhi/August 13

"I have been working here since 2005 and whenever any train passes by, one can feel the walls of the building shudder. The building is old and in a precarious state, but people continue to make alterations to the structure. None of the authorities concerned took note of the state of the building and construction," said Ram Niwas (50), who works at one of the factories in the complex, in which a portion of a building collapsed on Wednesday, killing a police officer, and injuring another.

Built before 1922, the complex is located barely 40m away from railway tracks and spans a 5,000-square yard area in Ram Bagh near Azad Market in north Delhi. HT visited the spot on Wednesday, and the building was visibly run down. Most of the walls were cracked, the cement had peeled off the walls, and balconies hung precariously on rusted, exposed metal beams.

In the records of the North Delhi Municipal Corporation's records, Azad market comes under the walled city area, which also includes areas such as Chandni Chowk, Jama Masjid, and other parts of Old Delhi.

A senior official of the north corporation's building department said, "No fresh construction or addition of floors are allowed in old buildings in the walled city area. In some cases, if there are renovations required, or the building has become so dangerous that a new construction is needed, the property owner has to seek permission from the civic body before starting any such work."

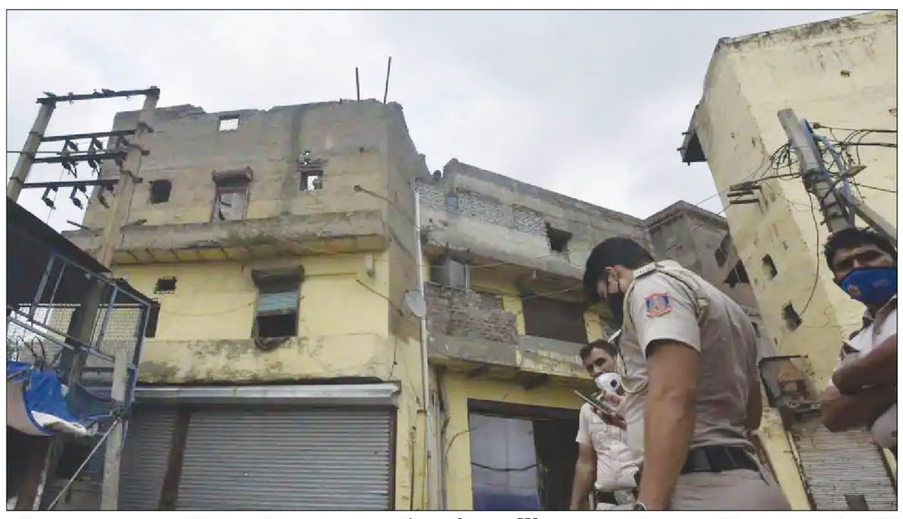

On Wednesday afternoon, mayor of the north corporation, Jai Prakash inspected the area and ordered a probe. "It is a case of illegal construction. The building is very old, and no permission was sought for constructions here. We are already conducting a survey of dangerous buildings in the north civic body's area. In the survey we have found that there are 125 old and dangerous buildings in the old city area. The survey is still underway, but I have ordered officials to check if this building features in the list of dangerous buildings," Jai Prakash, north corporation mayor said.

After a building is found dangerous, the civic body issues notice to the owner to either repair the property or demolish the portion of the building deemed "unsafe".

Sections of the complex are owned by a number of traders. The building also houses offices of real estate agents and godowns.

According to local traders, the building used to be a biscuit factory as far back as 1922. But it was shifted in 1970, and the property was bought by a local businessman, Shiv Shankar Gupta, who still owns a few portions of the property.

According to people working in the area, the building was dangerous. Gupta said the building portion which collapsed was purchased by a businessman in 2002. He said the businessman was making constructions on the upper floors.

"The building is very old, and some portions have become perilous. Authorities concerned were informed about the poor condition of the building, to no avail. Not even a single official of the civic body ever came here for an inspection, and no notice was served," Gupta said.

Labourers working at these factories also live in portions of the building complex. "We live in constant fear for our lives. Officials should make efforts to restore such old buildings," Roshan Sahu, a labourer at a factory in the building, said

Built before 1922, the complex is located barely 40m away from railway tracks and spans a 5,000-square yard area in Ram Bagh near Azad Market in north Delhi. HT visited the spot on Wednesday, and the building was visibly run down. Most of the walls were cracked, the cement had peeled off the walls, and balconies hung precariously on rusted, exposed metal beams. In the records of the North Delhi Municipal Corporation's records, Azad market comes under the walled city area, which also includes areas such as Chandni Chowk, Jama Masjid, and other parts of Old Delhi.

ASI dead, constable hurt after portion of building collapses in north Delhi

MM BUREAU

New Delhi/August 13

A 49-year-old assistant sub-inspector (ASI) died and a constable injured when an under-construction portion of a two-storey building collapsed in north Delhi's Azad Market on Wednesday morning. The two officers were in the building for verification of the tenants, officials said.

Police and municipal officials said a third floor was being constructed in the run-down building, but no permissions had been sought for the same.

North Delhi Municipal Corporation mayor Jai Prakash said, "The information we have received is that illegal constructions were being done in the building. I have ordered an enquiry into the matter to probe how and why the construction was happening. Any official found responsible for the laxity in the incident will not be spared."

The complex in which the building is located used to house a biscuit factory earlier, and is spread over nearly 5,000 square yards. The rooms in the building are owned by different persons. One of the occupants of the building said the rooms inside are used as toy assembling factories or godowns.

Deputy commissioner of police (north) Monika Bhardwaj said that in the wake of the forthcoming Independence Day celebration, the deceased ASI Zakir Hussain along with constable Debu Singh of the Bara Hindu Rao police station had gone to Azad Market for checking tenants living in the area.

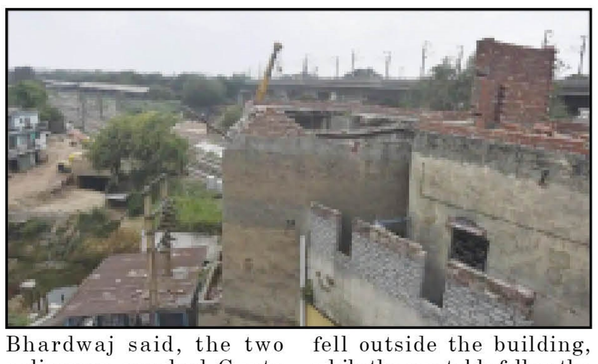

Around 10.30am, Bhardwaj said, the two policemen reached Gupta Building at Ram Bagh Road and while verifying tenants living there, noticed illegal constructions being done on the third floor of the building.

"The ASI and the constable went to the third floor to note details and take photographs of the illegal construction to send to the municipal corporation. The floor collapsed, and Hussain fell outside the building, while the constable fell on the second floor," Bhardwaj said.

A police officer associated with the investigation, speaking on the condition of anonymity, said Hussain was standing on the edge of the third floor terrace, while the constable was near the staircase when the floor caved in.

"Hussain fell almost 40-feet onto a cemented floor outside the building. Some portion of the collapsed wall also fell on his body, causing multiple injuries to his head and other body parts. His bike parked outside was also damaged," the officer said, quoting eyewitnesses.

The officer said the injured constable, with the help of some locals, rushed Hussain to Aruna Asaf Ali hospital, where he was declared dead on arrival. The constable was also admitted there and is undergoing treatment. Officials said he is out of danger.

"A case under sections 304A (causing death by negligence) and 288 (negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings) of the Indian Penal Code has been registered in connection with the mishap," Bhardwaj said.

She said that the portion of the building where the mishap took place is owned by a Civil Lines resident, while the contractor who was carrying out the illegal construction has also been identified.

Police said the building's ground and second floors are used as storehouses. Around four labourers who work in nearby factories and storehouses live on the first floor as tenants, while two kiosks that sell tobacco and groceries are located on the ground floor.

Hussain joined the Delhi Police in 1993 as a constable. Survived by his parents, brother, wife, a daughter and two sons, he was the sole bread-earner in the family. His wife and children live in Wazirabad village, Hussain's parents and brother live in a village in Uttar Pradesh's Meerut.

Mukesh Tokas be expelled from APP : Adesh Gupta

New Delhi/August 13

The organization in-charge of the Aam Aadmi Party of Delhi's RK Puram assembly constituency Mukesh Tokas has been arrested by the police on charges of raping a woman with the promise of marriage. Condemning the incident, Delhi BJP President Shri Adesh Gupta said that it is extremely shameful that the head of the Aam Aadmi Party and the CM of Delhi, Arvind Kejriwal, on the one hand make big claims about women's safety and on the other hand their party are found involved in serious cases like rape. Shri Gupta said that this is not new for the Aam Aadmi Party, in the past, many AAP leaders like Sharad Chauhan, Sandeep Kumar, Prakash Jarwal have been accused for sexual harassment and mibehavior with women. He said that the Kejriwal government's women's security system only appears in 3-4 pages advertisements in newspapers, on big hoardings, but not in reality and when the name of Aam Aadmi Party leaders comes up in cases like rape, sexual harassment, misbehavior with women, then CM Kejriwal takes silence. The Aam Aadmi Party has a long list of leaders who have proved that the Aam Aadmi Party is anti-women and CM Arvind Kejriwal gives protection to such leaders. Shri Gupta said that the Kejriwal government would have done politics on the women's security system but did not take any concrete steps on it. He said that the people of Delhi have chosen Chief Minister Kejriwal for public safety and not for protection of criminals. Chief Minister Kejriwal himself has to take this matter seriously. Delhi BJP demands that Mukesh Tokas be expelled from the Aam Aadmi Party with immediate effect and strict action should be taken against him.

Arvind Kejriwal to mark I-Day from Secretariat in view of Covid; guest list limited

MM BUREAU

New Delhi/August 13

This Independence Day, Delhi chief minister Arvind Kejriwal will hoist the tricolour and deliver his speech from the Delhi Secretariat, which will be telecast live via the government's social media handles, in the light of Covid-19 lockdown norms that prohibit gatherings. This would mark a break from the traditional celebrations at North Delhi's Chhatrasal Stadium where the chief minister participates in a parade —a tribute to the freedom fighters —followed by a flag-hoisting ceremony and a speech, in the presence of thousands of people. Most of the galleries are often occupied by school children. In his speech this year, a senior official in the chief minister's office (CMO) said, Kejriwal will focus on Delhi's fight against Covid-19—including a vote of thanks addressing all doctors, health care workers, sanitation workers, plasma donors and all "Covid warriors". He will not, in all likelihood, announce any new scheme or policy. At Chhatrasal Stadium last year, Kejriwal had announced the government's scheme of providing free rides to women in Delhi buses—which was implemented from September 29. "The guest list this year will be limited to 100. The flag will be hoisted in the outdoor area of the Secretariat. The chief minister is likely to give his speech from his office on the third floor. We are also considering using the open plazas on the first and second floors. A final call on that is yet to be taken. But there will be no parade or other celebrations, the CMO official said. Cabinet minister Gopal Rai said, "Keeping in mind the Covid-19 pandemic, the Delhi government has decided to cancel the mega cultural programme.

Delhi: 64-year-old man with five comorbidities fights Covid

MM BUREAU

New Delhi/August 13

A 64-year-old man coronavirus disease patient with at least four chronic illnesses -- cancer, kidney failure, heart disease and tuberculosis -- in addition to suffering a bout of pneumonia, all diagnosed in the past three months, was thought to have beaten Covid-19 and was discharged from Lok Nayak Hospital on Sunday, only to test positive for the virus again on Tuesday at a private hospital.

His family is perplexed by what doctors say could be a false negative or a false positive result, or simply a case of the second test picking up non-infective residual fragments of the viral genetic material from the past infection.

The patient, Raj Dev Dixit, is a retired professor who lives in outer Delhi's Najafgarh, where he runs an NGO called Garima that

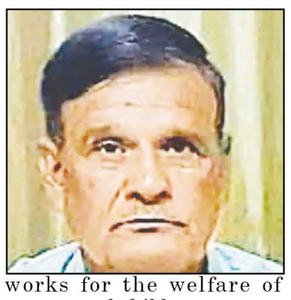

works for the welfare of women and children.

According to his son Amit Kumar, Dixit had no diagnosed illness and appeared healthy until three months ago. "He had none of the ailments he was diagnosed with in the past three months. He used to walk 10km every day," Kumar, who is an assistant director at the ministry of Ayush in Kolkata.

Kumar said that on May 18, Dixit was suddenly takenl ill and lost his appetite, which prompted his family to move him to a hospital where he was diagnosed with one failed kidney. "Over the next few weeks, he was diagnosed with myeloma (a cancer of the plasma cells) and his heart was found working at 20% of its capacity," Kumar said, adding that they got him admitted to Rajiv Gandhi Cancer Hospital in Rohini where he received chemotherapy and dialysis.

"As he grew weaker, we were told that he had developed tuberculosis and later, pneumonia, " Kumar said.

On July 17, Dixit tested positive for Covid-19 at the cancer hospital.Dixit was admitted to Lok Nayak Hospital on July 18 where he got plasma therapy for the coronavirus disease, and dialysis treatment eve[illegible] alternate day.

Dr Suresh K[illegible], director of L[illegible]yak Hospital, sai[illegible] was a "rare" cas[illegible]man with four chr[illegible]nesses, plus pneu[illegible]also contracting Covid-19.

"So far, we have admitted 7,600 Covid patients here, but only 60 of them had multiple comorbidities. While the others had a maximum of three comorbid conditions, Dixit's is a rare case of a man with five other diseases," Dr Kumar said.

"Dixit had a very low chance of survival. In such cases, usually, if one disease is treated, another starts causing trouble," he said. But on Saturday, when the patient was [illegible]ed for Covid for the [illegible]me at Lok Nayak[illegible]tal, the results c[illegible]ative and he was d[illegible]ed on Sunday. "[illegible] so encouraged [illegible]s particular result [illegible]at we decided that this case should feature in all leading international medical journals," the doctor said.

Delhi DCP Rajesh Deo among 121 recipients of MHA award

New Delhi/August 13

Officers linked to high-profile probes in the 2018 Elgar Parishad case, the 2020 Delhi riots case, the murder of rationalists in Maharashtra and Karnataka between 2013 and 2017 and the 2019 Muzaffarpur shelter home abuse case were among 121 recipients of the Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for 2020 announced on Wednesday. The officers include 15 people from the Central Bureau of Investigation (CBI), 10 each from Madhya Pradesh and Maharashtra, eight from Uttar Pradesh, and seven each from Kerala and West Bengal, a Union home ministry statement said. Rajnath Singh introduced the medal in 2018 when he was the Union home minister to promote professional standards in investigations and to recognise excellence by investigating officers. CBI additional superintendent, Subhash Ramrup Singh, was awarded for his role in finding the pistol suspected to have been used in rationalist Narendra Dabholkar's 2013 murder from the Arabian sea this year with the help of Norwegian divers. The ballistic report of the pistol is pending. Singh also investigated murders of writer MM Kalburgi (killed in 2015), journalist Gauri Lankesh (killed in 2017), and politician Govind Pansare (killed in 2015). Investigating agencies have claimed that all the murders were linked. Delhi Police deputy commissioner, Rajesh Deo, who is investigating cases related to the Delhi riots in February, was another recipient. Among the cases he is handling is one involving Jawaharlal Nehru University student Sharjeel Imam, who is jail on sedition charges for allegedly inciting people at anti-Citizenship (Amendment) Act protests.

SC seeks plan to install RFID at all toll points in Delhi

MM BUREAU

New Delhi/August 13

The Supreme Court has sought a plan from the civic agencies in Delhi for installing Radio Frequency Identity (RFID) system at 111 toll points to electronically deduct municipal toll tax and the environment compensation charge (ECC) from e-wallets of commercial vehicles. The plan has to be submitted by August 20, the court said.

The RFID system is already working at 13 toll points in Delhi. There are total 124 toll points in Delhi.

The Supreme Court order, passed on Monday, came on a suggestion by Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) -- an expert statutory body assisting the apex court in matters relating to environment and pollution. EPCA pointed out to the court that with the introduction of RFID technology, it has been possible to check the entry of commercial vehicles older

than 10 years. It has further improved online collection of the environment cess, EPCA said. The ECC was imposed on commercial vehicles by the Supreme Court to dissuade their entry into the Capital in order to reduce air pollution.

In its latest report dated January 28, 2020 submitted to the top court, EPCA said, "The results from the 13 entry points are substantial and suggest that the efforts to mitigate pollution have been rewarded. There is a 95% reduction in the total particulate load from trucks entering from 13 locations, as compared to 2015. There is 87-94% reduction in NOx loads from light-heavy duty vehicles entering from 13 locations." A bench of justices Arun Mishra, Br Gavai and Krishna Murari said, "It is agreed to by the learned counsel appearing for EPCA and the municipal corporation that on all the 111 entry points, RFID should be implemented and that can be done within the budget which is available. Let the steps be taken in this regard for implementation of the RFID and plan be placed on record before the next date of hearing on August 20."

Senior advocate Aparajita Singh assisting the Court as amicus curiae in this matter told HT, "The 13 locations were selected since 80% heavy vehicles used them to enter city. But in the latest assessment, the South Delhi Municipal Corporation (SDMC) informed the court that commercial traffic was increasing at the 111 other entry points to the Capital."

According to the EPCA report, the entry of commercial vehicles at 13 entry points has reduced from a maximum of 38,000 per day to 3,000 per day after the introduction of ECC and RFID system. "The number of commercial vehicles entering Delhi also reduced after the opening of Western and Eastern Peripheral expressways last year," Singh said. According to the EPCA report, "Vehicle owners (of commercial vehicles) are seeking new entry points to avoid payment of ECC."

To plug this loophole, the EPCA urged the apex court to extend RFID to all entry points of the Capital on an urgent basis. The project, to be undertaken by SDMC, will incur a cost of Rs 36 crore. For the first phase (in 13 locations), Rs 80.94 crore was spent. The total cost for both phases will be Rs 116.94 crore, which is within the stipulated Rs 120 crore sanctioned as project cost by the court, EPCA stated.

A senior official of the South Delhi Municipal Corporation (SDMC), which is the nodal agency to collect ECC in Delhi, said 111 more toll points are to be equipped with RFID for which the SC has asked to submit a report by August 20. "EPCA has convened a meeting to discuss the issue on Thursday. Once the Supreme Court clears the plan, we will start work on it," the official said, requesting anonymity.

ILD INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

CIN : L74899DL1984PLC019218 GSTIN : 07AAACI0149R1ZB

REGD. OFFICE : MGF House, 4/17-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

PH.: 41519433, 41520070 FAX : 41503479

Website: www.indialease.com, E-mail: info@indialease.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED IND AS FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(₹ in Lakhs except EPS)

S. NO.	PARTICULARS	For the Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	16.43	15.14	21.83	749.62
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Exceptional items and tax)	1.51	(10.76)	4.25	130.54
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items and before tax)	1.51	(10.76)	4.25	130.54
4	Net profit / loss for the period after tax	1.51	(10.76)	4.25	130.54
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensice Income (after tax)	1.87	(136.75)	4.29	4.67
6	Paid-up Equity Share Capital	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous financial year	-	-	-	(542.49)
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) Basic	0.01	(0.07)	0.03	0.89
	Diluted	0.01	(0.07)	0.03	0.89

Note :

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/yearly financial results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also at the Company's website www.indialease.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Place : New Delhi
Date : August 13, 2020

RAJIV GUPTA
CHAIRMAN
DIN : 00022964